

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 1071/2022

- श्रीराम यादव पुत्र श्री रामेश्वर लाल, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी गाँव नाहरवाड़ी पोस्ट मंडावरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू (राज.)
- प्रभु दयाल यादव पुत्र श्री सुखदेव राज, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी गाँव नाहरवाड़ी, पोस्ट मंडावरा, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू (राज.)

---याचिकाकर्ता

बनाम

- श्रीमती उषा शर्मा, मुख्य सचिव, सरकार सचिवालय, जयपुर (राज.)
- श्री आनंद कुमार, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सरकार सचिवालय, जयपुर (राज.)
- श्री लक्ष्मण सिंह कुरी, जिला कलेक्टर और अध्यक्ष, सार्वजनिक भूमि सुरक्षा प्रकोष्ठ झुंझुनू (राज.)
- राजस्थान राज्य, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, सरकार सचिवालय, जयपुर (राज.) के माध्यम से

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से	:	श्री अजय गुप्ता, अधिवक्ता, सुश्री संपत्ति शर्मा, अधिवक्ता के साथ।
प्रतिवादी की ओर से	:	श्री जी.एस. गिल, एएजी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), श्री मनोज कुमार, अधिवक्ता के साथ।

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्री न्यायमूर्ति भुवन गोयल

आदेश12/03/2024अवनिष झिंगन, जे [मौखिक]:-

1. यह अवमानना याचिका डी.बी. सिविल रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 3430/2022 में 28.04.2022 को पारित आदेश के निर्देशों के गैर-अनुपालन का तर्क देते हुए दायर की गई है। आदेश का परिचालन भाग नीचे पुनरुत्पादित है:

“उस दृष्टिकोण के मद्देनजर, जगदीश प्रसाद मीणा (सुप्रा) के मामले में खंडपीठ द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मद्देनजर, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है और याचिकाकर्ता पीएलपीसी के समक्ष एक प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वतंत्र हैं और प्रतिवादियों को उसी को दो महीने की अवधि के भीतर तय करने का निर्देश दिया जाता है।

यह आगे निर्देशित किया जाता है कि अतिक्रमण हटाने के लिए जांच में, जिन व्यक्तियों पर अतिक्रमण करने का आरोप है, उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।”

2. न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, याचिकाकर्ता ने 09.05.2022 को प्रतिनिधित्व दायर किया। प्रतिनिधित्व पर विचार किया गया। अतिक्रमणों को चिह्नित किया गया। 03.11.2022 को, मोहन लाल की संपत्ति को छोड़कर अतिक्रमण हटा दिए गए, क्योंकि मामला सिविल कोर्ट, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू के समक्ष विचाराधीन था और अंतरिम सुरक्षा दी गई थी।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि मोहन लाल ने एक पक्का गोदाम का निर्माण किया है, जो राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन पहाड़ के रूप में इंगित भूमि पर है और अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। तर्क यह है कि इस न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन नहीं किया गया है। प्रस्तुतीकरण यह है कि सिविल कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम सुरक्षा यह थी कि कानून के अनुसार कोई और कार्यवाही नहीं की जाएगी, फिर भी, अतिक्रमण नहीं हटाए गए। यह तर्क है कि खंडपीठ द्वारा अतिक्रमण हटाने के निर्देशों के बाद, सिविल कोर्ट को वाद पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

4. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने दलील पर भरोसा किया है, अर्थात् जवाब के पैरा 9, जिसे नीचे पुनरुत्पादित किया गया है:

“कि 3.11.2022 को, विवादित भूमि पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में टीम फिर से मौके पर पहुंची। आगे यह पाया गया कि सिविल जज,

उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू की अदालत ने मोहन लाल को अगले आदेश तक एक अंतरिम राहत दी थी, जबकि अन्य अतिक्रमणों को हटा दिया गया है। 12.10.2022 के आदेश की प्रति इसके साथ अनुलग्नक-आर/5 के रूप में चिह्नित और संलग्न है।”

5. हमने पक्षों के वकील को सुना और दलीलों का अवलोकन किया।
6. एकमात्र शिकायत यह उठाई गई है कि मोहन लाल ने विषय भूमि पर एक पक्का गोदाम का निर्माण किया है जिसे नहीं हटाया गया है। हालांकि, सिविल जज, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू द्वारा पारित 12.10.2022 (अनुबंध-आर/5) के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि मोहन लाल ने यह तर्क देने के लिए उपाय किया था कि कोई अतिक्रमण नहीं है और संपत्ति का सीमांकन सही नहीं था। अदालत ने अंतरिम सुरक्षा दी है और अतिक्रमण के संबंध में मुद्दा अभी भी विचाराधीन है, इसलिए, हमारी राय में, जानबूझकर अवज्ञा का कोई मामला नहीं बनता है।
7. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि खंडपीठ के निर्देशों के बाद, सिविल कोर्ट को सिविल वाद पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, हमारी राय में, एक व्यक्ति को अपने अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए कानून के तहत उपलब्ध कानूनी उपाय का लाभ उठाने का अधिकार है। पीआईएल में इस न्यायालय के समक्ष मुद्दा अतिक्रमण को हटाने के संबंध में था और वही कथित रूप से अतिक्रमणकर्ता के अधिकार को यह तर्क देने से नहीं छीनता है कि कब्जा वैध है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं का तर्क निराधार है।
8. अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है।
9. यह याचिका खारिज की जाती है।

(भुवन गोयल), जे

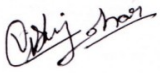
(अवनीश झिंगन), जे

एचएस/रिया/32

रिपोर्ट करने योग्य:- हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़